



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एम टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001



सत्यमेव जयते

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| क | अपील / फाइल नम्बर / Appeal / File No | मूल आदेश सं / OIO No | दिनांक / Date |
| | V2/ 38/RAJ/2020 | 2 & 3/D/Supdt/2019-20 | 03-05-2019 |

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-084-2020

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| आदेश का दिनांक / Date of Order: | 31.07.2020 | जारी करने की तारीख / Date of issue: | 04.08.2020 |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ महायुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मूजित:-
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellants & Respondent :-

M/s Inext Freight Forwarders, Shree Ram, 78-Aradhna Society, Airport Road, Rajkot-360007.

इस आदेश (अपील) में व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) बर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

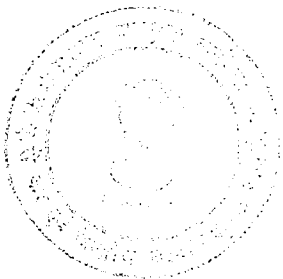
(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतलाए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टम) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहामाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म नं प्रपत्र EA-3 का चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। उनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपय 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपय तक अथवा 50 लाख रुपय से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपय, 5,000/- रुपय अथवा 10,000/- रुपय का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्ट्रार के नाम से किमी भी मार्बलित बैंक के बैंक द्वारा जारी खाता नंबर के ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। म्यगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवदन पत्र के साथ 500/- रुपय का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील बिन अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उत्तर में एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और उत्तर में कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपय 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपय तक अथवा 50 लाख रुपय से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपय, 5,000/- रुपय अथवा 10,000/- रुपय का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायुक्त रजिस्ट्रार के नाम से किमी भी मार्बलित बैंक के बैंक द्वारा जारी खाता नंबर के ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। म्यगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवदन पत्र के साथ 500/- रुपय का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवार्ती, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T. 7 में की जा सकेगी एवं इसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ मन्त्र कर (इसमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलवीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में मन्त्र करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलवीय प्राधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपीलियों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विनियम अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलवीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर भाग के 10 प्रतिशत (10%), जब भाग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, यद्यपि कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "भाग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 की अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की वी गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
यद्यपि यह कि इस धारा के प्रावधान विनियम (सं- 2) अधिनियम 2014 के अंश में पूर्व किमी अपीलवीय प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ स्थान अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार कोपत्तरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश को पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरतुक के अंतर्गत अवर मन्त्रि, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, विन मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जेवान दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section 35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से अंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंडार गृह से दूसरे अंडार गृह/पारगमन के दौरान, या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के नुकसान के मामलों में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी गृह या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर, बरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी गृह या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्यूटी कर्डेट इस अधिनियम एवं इसके विविध प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विन अधिनियम (सं- 2), 1994 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई वारिख अथवा महायार्थोधि पर या वाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रपण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां मन्त्र की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति मन्त्र की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ मन्त्र रकम एक लाख रूपये या इसमें कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि मन्त्र रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000/- का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्ना पृष्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलवीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case if the order covers various numbers of order in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क स्टिकर लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलवीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में बर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलवीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in की देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: ORDER-IN-APPEAL ::

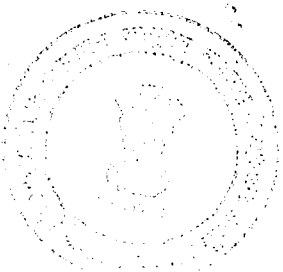
M/s. Inext Freight Forwarders, Rajkot (hereinafter referred to as "Appellant") filed appeal No. V2/38/RAJ/2020 against Order-in-Original No. 2 & 3/D/Supdt/2019-20 dated 3.5.2019 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Superintendent, Central GST Division, Rajkot-I. (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The brief facts of the case are that during the course of inquiry of the records of the Appellant, it was observed that the Appellant had earned freight income for providing service to their client for booking cargo space/ container space with shipping lines; that the Appellant charged more to their clients than what was paid to Shipping Lines and that the difference between amount charged to the clients and amount paid to shipping lines was liable to service tax under the category of 'Business Auxiliary Service'; that the Appellant failed to pay Service Tax on said freight income.

2.1 Show Cause Notice No. V.84(4)-5/MP/D/Supdt/18-19 dated 12.4.2018 was issued to the Appellant for the year 2015-16, calling them to show cause as to why Service Tax of Rs. 1,86,694/- should not be demanded and recovered from them on freight income under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (*hereinafter referred to as "Act"*) along with interest under Section 75 of the Act and proposing imposition of penalty under Sections 76 and 77 of the Act.

2.2 Subsequently, a Statement of demand No. V.84(4)-10/MP/D/Supdt/18-19 dated 26.3.2019 was issued to the Appellant for the period 2016-17 (upto June, 2017), calling them to show cause as to why Service Tax of Rs. 6,30,692/- should not be demanded and recovered from them under Section 73(1) of the Act, along with interest under Section 75 *ibid* and proposing imposition of penalty under Sections 76 and 77 of the Act.

2.3 The above Show Cause Notice and Statement of Demand were adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order confirming demand of Service Tax totally amounting to Rs. 8,17,386/- under Section 73(1) of the Act along with interest under Section 75 of the Act and imposed penalty totally amounting to Rs. 81,738/- under Section 76 of the Act and Rs. 20,000/- under Section 77 of the Act.



3. Aggrieved, the Appellant has preferred this appeal on 16.6.2020 along with application for condonation of delay.

3.1 In application for condonation of delay, the Appellant has requested to condone delay in filing appeal on the ground that they had given appeal assignment to their tax consultant but he delayed it; that now they have changed their tax consultant to complete appeal process.

4. I find that the impugned order was issued on 3.5.2019 by the adjudicating authority. The Appellant received the impugned order on 14.5.2019, as reported by the Superintendent(Adj), Central GST Division-I, Rajkot vide letter F.No. IV/16-2/Misc/Adj/2018-19 dated 30.7.2019. The Appellant was required to file appeal within 2 months from the receipt of the said order i.e. on or before 14.7.2019, as stipulated under Section 85(3A) of the Act. However, the Appellant filed Appeal on 16.6.2020, i.e. after 11 months from due date. This appellate authority has powers to condone delay of one month in filing of appeal, over and above two months mentioned above, if sufficient cause is shown, as per proviso to Section 85(3A) *ibid*. I find that there is a delay of 11 months in filing the appeal over and above the normal period of 2 months. Thus, appeal filed beyond the time limit prescribed under Section 85 *ibid* cannot be entertained.

5. This appellate authority is a creature of the Statute and has to act as per the provisions contained in the Act. This appellate authority, therefore, cannot condone delay beyond the period permissible under the Act. When the legislature has intended the appellate authority to entertain the appeal by condoning further delay of only one month, this appellate authority cannot go beyond the power vested by the legislature. My views are supported by the following case laws :

(i) The Hon'ble Supreme Court in the case of **Singh Enterprises** reported as 2008 (221) E.L.T. 163 (S.C.) has held as under:

"8. ...The proviso to sub-section (1) of Section 35 makes the position crystal clear that the appellate authority has no power to allow the appeal to be presented beyond the period of 30 days. The language used makes the position clear that the legislature intended the appellate authority to entertain the appeal by condoning delay only upto 30 days after the expiry of 60 days which is the normal period for preferring appeal. Therefore, there is complete exclusion of Section 5 of the Limitation Act. The Commissioner and the High Court were therefore justified in holding that there was no power to condone the delay after the expiry of 30 days period.

(ii) In the case of **Makjai Laboratories Pvt Ltd** reported as 2011 (274) E.L.T. 48 (Bom.), the Hon'ble Bombay High Court held that the Commissioner

(Appeals) cannot condone delay beyond further period of 30 days from initial period of 60 days and that provisions of Limitation Act, 1963 is not applicable in such cases as Commissioner (Appeals) is not a Court.

(iii) The Hon'ble High Court of Delhi in the case of Delta Impex reported as 2004 (173) E.L.T. 449 (Del) held that the Appellate authority has no jurisdiction to extend limitation even in a "suitable" case for a further period of more than thirty days.


6. I find that the provisions of Section 85 of the Finance Act, 1994 are *pari materia* with the provisions of Section 35 of the Central Excise Act, 1944 and hence, the above judgements would be squarely applicable to the present appeal also.

7. By respectfully following the above judgements, I hold that this appellate authority cannot condone delay beyond further period of one month as prescribed under proviso to Section 85(3A) of the Act. Thus, the appeal filed by the Appellant is barred by limitation and hence, not maintainable.


8. I, therefore, dismiss the appeal on limitation and uphold the impugned order.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

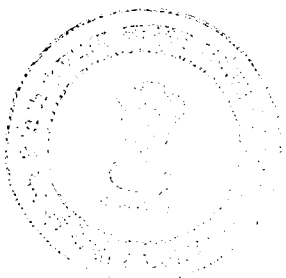

(GOPI NATH)
Commissioner(Appeals)

Attested


(V.T.SHAH)
Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

| | |
|--|--|
| To, M/s Inext Freight Forwarders, 'Shree Ram', 78, Aradhna Society, Airport Road, Rajkot. | सेवा में, मे. इनेक्स्ट फ्रेट फोरवरदर्स, 'श्री राम', 78, आराधना सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, राजकोट. |
|--|--|



प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अधीक्षक, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल, राजकोट-1, राजकोट आयुक्तालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फाइल।

